वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017-2018

Har Kadam aap ke Saath

इलाहाबाद बैंक
विश्वास की परंपरा

ALLAHABAD BANK
A tradition of trust

www.allahabadbank.in

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001
HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001
www.allahabadbank.in

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2017-18

विषय-सूची / Contents

	पृष्ठ सं. / Page No.
• निदेशक, लेखापरीक्षक, महाप्रबंधक गण आदि/ Directors, Auditors, General Managers etc.	02-04
• बैंक के निदेशकों की रिपोर्ट/ Directors' Report of the Bank	05-23
• प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण/ Management Discussion and Analysis	24-40
• व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट/ Business Responsibility Report	41-51
• बासेल - III प्रकटीकरण/ Basel - III Disclosures	52-119
• कारपोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट/ Report on Corporate Governance	120-154
• कारपोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र/ Auditors' Certificate on Corporate Governance	155
• सीईओ और सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र/ Compliance Certificate by CEO and CFO	156-157
• बैंक के वित्तीय विवरण/ Financial Statements of the Bank	158-221
• बैंक के लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report of the Bank	222-223
• समेकित वित्तीय विवरण/ Consolidated Financial Statements	224-258
• समेकित वित्तीय विवरण पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट/ Auditors' Report on Consolidated Financial Statements	259-262
• इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाभांश भुगतान हेतु अधिदेश फार्म/ Mandate form for payment of dividend electronically	263-264

इलाहाबाद बैंक
ALLAHABAD BANK

प्रधान कार्यालय : 2, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700 001

HEAD OFFICE: 2, NETAJI SUBHAS ROAD, KOLKATA- 700 001

निदेशक मंडल /BOARD OF DIRECTORS (यथास्थिति/AS ON 31-03-2018)

1.	श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन *	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
	Smt. Usha Ananthasubramanian *	Managing Director and CEO
2.	श्री एन. के. साहू	कार्यपालक निदेशक
	Shri N. K. Sahoo	Executive Director
3.	श्री एस. हरिशंकर	कार्यपालक निदेशक
	Shri S Harisankar	Executive Director
4.	श्री राजीव रंजन	सरकार द्वारा नामित निदेशक
	Shri Rajeev Ranjan	Government Nominee Director
5.	श्री विवेक दीप	भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
	Shri Vivek Deep	RBI Nominee Director
6.	प्रो. राधा आर. शर्मा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
	Prof. Radha R. Sharma	Part Time Non-Official Director
7.	श्री गौतम गुहा	अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
	Shri Gautam Guha	Part Time Non-Official Director
8.	डॉ. बिजय कुमार साहू	शेयरधारक निदेशक
	Dr. Bijaya Kumar Sahoo	Shareholder Director
9.	श्री सारथ सूरा	शेयरधारक निदेशक
	Shri Sarath Sura	Shareholder Director
10.	डॉ. पार्थप्रतिम पाल	शेयरधारक निदेशक
	Dr. Parthapratim Pal	Shareholder Director

* 6 मई 2017 से बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

* Managing Director and CEO of the Bank w.e.f. 6th May, 2017.

श्री राकेश सेठी ने 30.04.2017 को अधिवर्षिता प्राप्त करने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अपना कार्यकाल पूरा किया।

Shri Rakesh Sethi completed his tenure of Chairman and Managing Director on attaining the age of superannuation on 30.04.2017.

लेखा-परीक्षक/AUDITORS

1.	**मे. राजू एंड प्रसाद**	सनदी लेखाकार
	M/s Raju & Prasad	*Chartered Accountants*
2.	मे. कंसल सिंगला एंड एसोसिएट्स	सनदी लेखाकार
	M/s Kansal Singla & Associates	*Chartered Accountants*
3.	मे. नंदी हलदर एंड गांगुली	सनदी लेखाकार
	M/s Nandy Halder & Ganuli	*Chartered Accountants*
4.	मे. दे एंड बोस	सनदी लेखाकार
	M/s De & Bose	*Chartered Accountants*
5.	मे. जीएनएस एंड एसोसिएट्स	सनदी लेखाकार
	M/s GNS & Associates	*Chartered Accountants*

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट/REGISTRAR & SHARE TRANSFER AGENT

सीबी मैनेजमेंट सर्विसेज (प्रा) लि.
(यूनिटः इलाहाबाद बैंक)
पी-22 बंडेल रोड,
कोलकाता-700019
दूरभाष सं. : 033-40116700,
फैक्स सं. : 033-40116739
ईमेलः rta@cbmsl.com

CB Management Services (P) Ltd.
(Unit: Allahabad Bank)
P-22, Bondel Road,
Kolkata-700019.
Telephone No. : 033-40116700
Fax No. : 033-40116739
Email : rta@cbmsl.com

निदेशक मंडल
Board of Directors

श्रीमती उषा अनन्तसुब्रह्मण्यन
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Smt. Usha Ananthasubramanian
Managing Director & Chief Executive Officer

श्री एन. के. साहू
कार्यपालक निदेशक
Shri N.K. Sahoo
Executive Director

श्री एस. हरिशंकर
कार्यपालक निदेशक
Shri S. Harisankar
Executive Director

श्री राजीव रंजन
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri Rajeev Ranjan
Government Nominee Director

श्री विवेक दीप
भा.रि.बैंक द्वारा नामित निदेशक
Shri Vivek Deep
RBI Nominee Director

प्रो. राधा आर. शर्मा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Prof. Radha R. Sharma
Part Time Non-Official Director

श्री गौतम गुहा
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक
Shri Gautam Guha
Part Time Non-Official Director

डॉ. बिजय कुमार साहू
शेयरधारक निदेशक
Dr. Bijaya Kumar Sahoo
Shareholder Director

श्री सारथ सूरा
शेयरधारक निदेशक
Shri Sarath Sura
Shareholder Director

डॉ. पार्थप्रतिम पाल
शेयरधारक निदेशक
Dr. Parthapratim Pal
Shareholder Director

महाप्रबंधक
General Managers

श्री संजय अग्रवाल
Shri Sanjay Aggarwal

श्री पार्थदेब दत्ता
Shri Parthadeb Datta

श्री विपुल सिंगला
Shri Vipul Singla

श्री विकास कुमार
Shri Vikas Kumar

श्री एस. एल. जैन
Shri S. L. Jain

श्री सुधांशु गौड़
Shri Sudhanshu Gaur

श्री पी.सी. शर्मा
Shri P. C. Sharma

श्री इमरान ए सिद्दिकी
Shri Imran A Siddiqui

श्री एस.वी. एल. एन. नागेश्वर राव
Shri S.V.L.N. Nageswara Rao

श्री एन.एन. कुमार साहा
Shri N. N. Kumar Saha

श्री दिनेश कुमार
Shri Dinesh Kumar

श्री के.नन्दकुमार
Shri K. Nandhakumar

श्री बि. कु. मित्र
Shri B. K. Mitra

श्री मुक्ति नाथ पटेल
Shri Mukti Nath Patel

श्री सुनील बरन जेना
Shri Sunil Baran Jena

श्री संजीव कुमार सूरी
Shri Sanjeev Kumar Suri

श्री अरुण कुमार पाण्डेय
Shri Arun Kumar Pandeya

श्री बनम्बर साहू
Shri Banambar Sahoo

श्री विवेक. एम. पडगांवकर
Shri Vivek M. Padegaonkar

श्री रविन्दर सिंह
Shri Ravinder Singh

इलाहाबाद बैंक

निदेशकों की रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2017-18 (वित्तीय वर्ष 18) के दौरान, बैंक का वैश्विक व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 5.57% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹3,80,040 करोड़ (₹3.80 लाख करोड़) तक पहुंच गया। बैंक का अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय वर्ष-दर-वर्ष 12.871 करोड़ रहा और इसने विदेशी अग्रिम में 12.82% वर्ष-दर-वर्ष गिरावट के कारण -8.91% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। मार्च, 17 के अंत में बैंक की वैश्विक जमा राशि 5.81% की वृद्धि के साथ ₹2,13,604 करोड़ रही और सकल अग्रिम 5.27% की वृद्धि के साथ ₹1,66,436 करोड़ रहा। आपका बैंक कम लागत की जमाओं पर ध्यान केंद्रित करता रहा जिसके परिणामस्वरूप कासा जमा में वर्ष-दर-वर्ष 7.45% की अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है और 31मार्च, 2018 को यथास्थिति यह ₹98,419 करोड़ रही। तदनंतर, यथास्थिति 31मार्च, 2018 को कासा अंश पिछले वर्ष के 45.79% की तुलना में बढ़कर 46.50% हो गया है।

बैंक का परिचालनगत लाभ अग्रिम पोर्टफोलियों पर दबाव और परिणामी रिवर्सल/ ब्याज न लगाने के कारण वर्ष-दर-वर्ष 11.08% कम हुआ है। यह वित्तीय वर्ष 18 के दौरान ₹3438 करोड़ रहा। निवल लाभ के रूप में, वित्तीय वर्ष 18 में हानि की मात्रा में वृद्धि हुई क्योंकि उच्च्तर प्रावधान 94.07% था और निवल ब्याज आय स्तरों में कमी आई थी। पिछले वर्ष की ₹314 करोड़ की निवल हानि की तुलना में वित्तीय वर्ष 18 में निवल हानि बढ़कर कर ₹4674 करोड़ हुई। बैंक का सीआरएआर वित्तीय वर्ष 17 के 11.45% के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 18 में 8.69% रहा, । थोक जमाराशियों में कटौती के कारण, जमा लागत वित्तीय वर्ष 17 के 5.94% से कम होकर वित्तीय वर्ष 18 में 5.33% हो गई।

इस पृष्ठभूमि में, आपके निदेशकों को 2017-18 हेतु लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों सहित बैंक का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

हमारा कार्यनिष्पादन

ए. वित्तीय विशिष्टताएं

ए.1. तुलन पत्र

ALLAHABAD BANK

DIRECTORS' REPORT

During the financial year 2017-18 (FY18), the Bank's global business reached the level of ₹3,80,040 crore (₹3.80 lakh crore), registering a Y-o-Y growth of 5.57%. The Bank's international business stood at ₹12,871 crore and recorded a negative Y-o-Y growth of -8.91% on account of 12.82% Y-o-Y drop in overseas advances. Global deposits of the Bank stood at ₹2,13,604 crore which increased by 5.81% and gross advances grew by 5.27% and stood at ₹1,66,436 crore as at the end of Mar'18. Your Bank's continued focus on low cost deposits resulted in a healthy Y-o-Y growth of 7.45% in CASA deposits and the build-up stood at ₹98,419 crore as on 31st Mar'18. Subsequently, CASA share improved to 46.50% as on 31st Mar'18 from 45.79% a year ago.

The Bank's operating profit decreased by 11.08% Y-o-Y on account of stress on advances portfolio and resultant reversal/ non-booking of interest. It stood at ₹3438 crore during FY18. In terms of net profit, the quantum of losses increased in FY18 as provisions were higher by 94.07% and there was a decrease in net-interest income levels. Net loss rose to ₹4674 crore in FY18 as compared to a net loss of ₹314 crore a year ago. The Bank's CRAR stood at 8.69% in FY18 as compared to 11.45% in FY17. Owing to reduction in bulk deposits, the cost of deposits decreased to 5.33% during FY18 from 5.94% in FY17.

Against this backdrop, your Directors take pleasure in placing the Bank's Annual Report for 2017-18 along with audited annual financial statements.

OUR PERFORMANCE

A. FINANCIAL HIGHLIGHTS

A.1. BALANCE SHEET

(राशि ₹ करोड़ में)/(Amount ₹ in Crore)

मानदंड / Parameter	31 मार्च '17 31ST MAR'17	31 मार्च '18 31ST MAR'18	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि % Y-O-Y GROWTH %
कुल व्यवसाय / Total Business	359974	380040	5.57
कुल जमाराशियां / Total Deposits	201870	213604	5.81
सकल अग्रिम / Gross Advances	158103	166436	5.27

ए.2. लाभ

A.2. PROFIT

(राशि ₹ करोड़ में)/(Amount ₹ in Crore)

मानदंड / Parameter	31 मार्च' 17 31ST MAR' 17	31 मार्च' 18 31ST MAR' 18	वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि % Y-O-Y GROWTH %
परिचालनगत लाभ / Operating Profit	3867	3438	-11.08
प्रावधान / Provision	4180	8113	94.07
निवल लाभ/(हानि) / Net Profit/(Loss)	(314)	(4674)	

ए.3. प्रमुख अनुपात

A.3. KEY RATIOS

मानदंड / Parameter	मार्च '17/Mar'17	मार्च '18/Mar'18
जमा लागत/Cost of Deposits	5.94	5.33
निधि लागत/Cost of Funds	5.74	5.23
निधि पर प्रतिफल/Yield on Funds	8.41	7.61
उधार लागत/Cost of Borrowings	3.52	4.15
निवल ब्याज मार्जिन/Net Interest Margin	2.54	2.20
आस्तियों पर प्रतिफल/Return on Assets	-0.13	-1.96
आय के सापेक्ष लागत अनुपात/Cost to Income Ratio	51.25	53.69

बी. आस्ति गुणवत्ता

विभिन्न समष्टि आर्थिक और अन्य कारकों के कारण आस्ति गुणवत्ता में सतत दबाव का सामना करने के कारण वित्तीय वर्ष 18 भारतीय बैंकिंग उद्योग के लिए एक चुनौतीपूर्ण वर्ष था। यथास्थिति 31 मार्च, 2018 को बैंक का सकल एनपीए ₹26562.76 करोड़ (विव17: ₹20687.83करोड़) और निवल एनपीए ₹12229.13 करोड़ (विव17: ₹13433.51 करोड़) रहा। अनुपात के रूप में सकल एनपीए प्रतिशत औए निवल एनपीए प्रतिशत क्रमशः 15.96% (विव17: 13.09%) और 8.04% (विव 17: 8.92%) था।

बैंक ने नए स्लिपेज रोकने के लिए विभिन्न उपाय शुरू किए और इसे विव17 के ₹11417.00 करोड़ की तुलना में विव '18 में ₹12903.28 करोड़ तक सीमित रखा। प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) भी विव17 में 50.11% की तुलना में विव18 में बढ़कर 62.91% हुआ।

आस्ति गुणवत्ता सुधारने हेतु बैंक ने सतत वसूली अभियान शुरु किए और 28.58% की वृद्धि के साथ ₹3379.08 करोड़ वसूल की, इसमें से, ठोस प्रयासों, दैनिक मॉनिटरिंग और खाता विनिर्दिष्ट रेजोल्यूशन योजना के कारण ₹2071.86 करोड़ की नकद वसूली हुई। उपर्युक्त अवधि के दौरान एनपीए खातों में कुल कमी ₹7028.32 करोड़ थी।

बैंक ने कृषि क्षेत्र के मौजूदा माड्यूल की तरह अनुभव पर आधारित नियम के रूप में अन्य एनपीए खातों हेतु ओटीएस माड्यूल में निर्धारित सीमा ₹10.00 लाख से बढ़ाकर ₹15.00 लाख करते हुए मौजूदा ओटीएस योजनाओं में समुचित संशोधन किए हैं। इसके फलस्वरूप अप्रतिभूत छोटे उधार खातों के निपटान में तेजी आई है। इसके अतिरिक्त मासिक आधार पर निदेशक मंडल/एमसीबीओडी को सूचनार्थ प्रक्रिया नोट प्रस्तुत करने के अध्यधीन धोखाधड़ी वाले घोषित खातों में ओटीएस की संस्वीकृति के अधिकार भी विभिन्न प्राधिकारियों, किंतु एफजीएमएलसीसी से कम नहीं, को प्रत्यायोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त ऋण मुक्ति शिविर के माध्यम से समझौता/समाधान वार्ता तथा उधारकर्ताओं के साथ परस्पर बैठक के रूप में अन्य महत्वपूर्ण साधन अपनाए गए थे।

तथापि, ₹1.00 करोड़ से अधिक के बड़े उधार खातों की वसूली स्पष्ट कारणों से बैंक हेतु बाधित बनी रही। इन खातों की अनुवर्ती कार्रवाई, मॉनिटरिंग और वसूली हेतु ऑनलाइन माड्यूल "पार्थ" (पॉर्टल फॉर एसेट रेजोल्यूशन थ्रू हॉट चेज) अपनाया गया जो इस क्षेत्र में समाधान सुनिश्चित करने में बहुत उपयोगी था। अब पार्थ के कवरेज का विस्तार ₹50.00 लाख और अधिक बकाया वाले एनपीए खातों तक किया गया है।

B. ASSET QUALITY

FY18 was a challenging year for the Indian Banking Industry due to continued stress faced in asset quality on account of various macroeconomic and other factors. As on 31st Mar'18, Gross NPA of the Bank stood at ₹26562.76 crore (FY17: ₹20687.83 crore) and Net NPA remained at ₹12229.13 crore (FY17: ₹13433.51 crore). In terms of ratio, Gross NPA Percentage and Net NPA Percentage were 15.96% (FY17: 13.09%) & 8.04% (FY17: 8.92%) respectively.

The Bank initiated various measures to arrest fresh slippage and restricted it to ₹12903.28 crore for the FY18 compared to ₹11417.00 crore for the FY17. Provision Coverage Ratio (PCR) also improved to 62.91% in FY18 from 50.11% in FY17.

To improve asset quality, the Bank initiated consistent recovery drive and recovered ₹3379.08 crore, out of which Cash Recovery was Rs. 2071.86 crore with a growth of 28.58 % due to concerted efforts, daily monitoring and account specific resolution plan. During the aforesaid period, total Reduction in NPA accounts stood at ₹7028.32 crore.

The Bank also made suitable amendments in existing OTS schemes by increasing the cut off limit from ₹10.00 lacs to ₹15.00 lacs in OTS module for other NPA a/cs in Thumb Rule module as in existing module for Farm Sector. This resulted in accelerated settlement of Unsecured small borrowal accounts. Further, power to sanction OTS in fraud declared accounts was also delegated to various authorities but not below the level of FGMLCC, subject to placement of process notes to Board of Directors/ MCBOD for information on monthly basis.

Further, compromise/negotiated settlement through Rin Mukti Shivir and one-to-one meeting with borrowers was adopted as another vital tool to tackle NPAs.

However, recovery in big borrowal accounts above ₹1.00 crore remained a constraint for the Bank for obvious reasons. For follow-up, monitoring and recovery in these accounts, online module "PARTH" (Portal for Asset Resolution through Hot chase) was introduced which was very useful in assuring resolution in this segment. Now the coverage in PARTH has been extended to NPA accounts having outstanding above ₹50 lakhs.

एनपीए खातों की कारगर और समय से मानिटरिंग तथा ₹50.00 लाख और अधिक के लेजर शेष वाले एनपीए खातों में विधिवत प्रक्रिया के अनुवर्तन हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर समर्पित कार्यपालकों के साथ वार रूम अवधारणा आरंभ की गई है।

बैंक की 9 आस्ति वसूली प्रबंधन शाखाएं (एआरएमबी) भी है, जो अनन्य रूप से एनपीए समाधान का कार्य करती हैं।

वित्तीय वर्ष 18 में की गई पहल

- बैंक ने ₹50.00 लाख से अधिक बकाया वाले बड़े उधार खातों की प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल "पार्थ" लागू किया है। ऐसे उधारकर्ताओं पर मजबूत पकड़ और सामयिक विधिक कार्रवाई से वसूली हेतु इन खातों को नियंत्रित करने में हमारी पैठ बढ़ी है।
- बैंक ने ₹50.00 लाख से अधिक बकाया वाले बड़े एनपीए खातों में समुचित प्रक्रिया की गहन मानिटरिंग हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर समर्पित कार्यपालकों (दो सहायक महाप्रबंधक और एक मुख्य प्रबंधक) के साथ "वार रूम" आरंभ किया है।
- अन्य एनपीए खातों में अनुभव पर आधारित नियम पद्धति हेतु निर्धारित सीमा ₹10.00 लाख से बढ़ाकर ₹15.00 लाख करते हुए ओटीएस माड्यूल में समुचित संशोधन किए गए हैं।
- मासिक आधार पर निदेशक मंडल/एमसीबीओडी को सूचनार्थ प्रक्रिया नोट प्रस्तुत करने के अध्यधीन धोखाधड़ी वाले घोषित खातों में ओटीएस की संस्वीकृति के अधिकार भी विभिन्न प्राधिकारियों, किंतु एफजीएमएलसीसी से कम नहीं, को प्रत्यायोजित किए गए हैं । इसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी घोषित खातों में ₹6.52 करोड़ के लेजर शेष और ₹4.02 करोड़ की समझौता राशि वाले 71 ओटीएस प्रस्तावों का समाधान किया गया है।
- एनपीए खातों में पैठ बढ़ाने हेतु मंडलों/एफजीएमओ के साथ दैनिक वसूली की मॉनिटरिंग शुरू की गई।
- बैंक ने पिछले वर्ष सभी शाखाओं को सम्मिलित कर 12 वसूली कैम्पों (प्रत्येक माह एक कैम्प) का आयोजन किया। इसमें ₹3564.55 करोड़ की वसूली हुई, जो वसूली की दृष्टि से बहुत ही सफल रहा। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के विपणन हेतु वसूली एजेंसियों और बैंकिग प्रतिनिधियों की सेवाओं का समुचित प्रयोग किया गया।
- वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने ₹1123.18 करोड़ के लेजर शेष वाले और ₹700.32 करोड़ की समझौता राशि के 73198 समझौता प्रस्ताव संस्वीकृत किए।
- बैंक ने राष्ट्रीय लोक अदालत में सक्रिय सहभागिता की और ₹314.56 करोड़ के बाकाया वाले 26950 मामलों का निपटान किया।
- वर्ष भर प्रभारित अचल और चल प्रतिभूतियों की ई-नीलामी की गई। संशोधित सरफेसी अधिनियम का लाभ उठाते हुए या तो प्रवर्तन एजेंसियों की मदद से या संबंधित डीएम/सीएमएम के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अचल संपत्तियों के वास्तविक कब्जे पर बल दिया गया। इस कार्रवाई से बैंक के पास वास्तविक कब्जे के अंतर्गत संपत्तियों की नीलामी में वृद्धि हुई है।
- प्रत्येक डीआरटी केन्द्र के नोडल अधिकारी को दैनिक आधार पर विधिक मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का कार्य सौंपा गया है ताकि डिक्री प्राप्त करने और निष्पादन करने में विलम्ब को कम किया जा सके।

For effective and timely monitoring of NPA accounts and follow up of due process in NPA accounts having Ledger balance of ₹50.00 Lacs and above, concept of "War Room" has been introduced at Head Office level with dedicated executives.

The Bank also has 9 Asset Recovery Management Branches (ARMBs) which function exclusively for resolving NPAs.

Initiatives taken during FY18

- The Bank introduced Online Module "PARTH" for effective monitoring of big borrowal accounts having outstanding above Rs. 50.00 lacs. Hot chase of such borrowers and timely legal action increased our penetration rate to crack these accounts for recovery.
- Bank introduced "War Room" with dedicated executives (Two Asstt. General Managers and One Chief manager) at Head Office level for close monitoring of due process in NPA accounts having outstanding balance of ₹50.00 lacs and above.
- Suitable amendments in OTS module by increasing the Cut Off limit from ₹10.00 Lacs to ₹15 Lacs for Thumb Rule method in other NPA accounts.
- Power to sanction OTS in fraud declared accounts was also delegated to various authorities but not below the level of FGMLCC, subject to placement of process notes to Board of Directors/ MCBOD for information on monthly basis. This resulted in settlement of 71 OTS proposals with ledger balance of ₹6.52 Cr and Compromise sum of ₹4.02 Crore in Fraud declared accounts.
- Monitoring of daily recovery was introduced with Zones/ FGMOs to improve penetration in NPA accounts.
- The Bank organized 12 Recovery Camps in the previous year (one camp in each month) involving all the branches. This step was very successful in terms of recovery that amounted to ₹3564.55 crore. Services of Recovery Agencies and Banking Correspondents were properly utilized for marketing of One Time Settlement Schemes (OTS).
- During the FY18 Bank sanctioned 73198 Compromise cases with ledger balance of ₹1123.18 crore and compromise amount of ₹700.32 Crore.
- The Bank participated in National Lok Adalat actively and settled 26950 cases having outstanding of ₹314.56 crore.
- E-auctions of charged immovable & movable securities were carried out through-out the year. Special thrust was given in taking physical possession of immovable properties either with the help of Enforcement Agencies or by moving application before the concerned DM/CMM taking advantage of amended SARFAESI Act. This step resulted into increased auction of properties under physical possession of the Bank.
- Nodal Officer at each DRT centre was assigned the role of follow-up of legal cases on daily basis so as to minimize delay in obtaining decrees and execution.

- बढ़ते एनपीए से निपटने का एक अन्य उपलब्ध विकल्प था एआरसी को दीर्घकालिक/जटिल खातों की ब्रिकी। इसका उपयोग किया गया और वित्तीय वर्ष 18 के दौरान विभिन्न एजेंसियों को 216 खाते और ₹2539.21 करोड़ मूल्य की संपत्ति बेची गई थी।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु पहल की गई। समुचित सावधानी प्रक्रिया पूरी करने के बाद, पहचान किए गए उधारकर्ताओं को बैंक द्वारा इरादतन चूककर्ता के रूप में घोषित किया गया और यह संख्या मार्च'17 के 101 से ढाई गुना बढ़ कर अब 257 हो गई है।
- प्रभावी और बेहतर मानिटरिंग हेतु, सभी उधारखातों को मुख्यतः चार शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात (i) ₹50,000 से कम (ii) ₹50,000 से ₹15.00 लाख (iii) ₹15.00 लाख से ₹1.00 करोड़ और (iv) ₹1.00 करोड़ से अधिक। जबकि प्रथम दो चरणों में ओटीएस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है, अन्य अतिरिक्त विकल्प जैसे सरफेसी के अंतर्गत बिक्री, इरादतन चूककर्ता की घोषणा, रिस्ट्रक्चरिंग, डीआरटी में वाद दाखिल करना अगली दो श्रेणियों में अत्यंत विधिवत रूप से अपनाया जाता है। उच्च मूल्य के एनपीए खातों में वसूली हेतु महत्वपूर्ण साधन के रूप में आईबीसी/ एनसीएलटी के माध्यम से समाधान का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ₹1.00 करोड़ से अधिक के बकाया वाले उधार खातों में मंडलीय प्रमुखों और एफजीएम के साथ मासिक वीसी बैठक की जाती है और "साध्य खातों" की पहचान की जाती है जिसमें तिमाही के अंदर बदलाव/वसूली की संभावना हो। समाधान सुनिचित करने हेतु इन खातों के संबंध में दैनिक आधार पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 18 के दौरान बैंक ने आईबीसी के अंतर्गत समाधान हेतु ₹12566.11 करोड़ की राशि वाले 65 एनपीए खाते नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लि. (एनईएसएल) को भेजे हैं।
- आईबीसी के अंतर्गत विचारित सूचना उयोगिता सेवाओं का प्रयोग करने हेतु नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस लि. (एनईएसएल) के साथ टाईअप किया गया है।

अपनाई जानेवाली नई पहल

- अनन्य रूप से एनसीएलटी संदर्भित मामलों की निगरानी हेतु प्रधान कार्यालय में एक पृथक "एनसीएलटी कक्ष" स्थापित किया जा रहा है।
- बेहतर बोलियां प्राप्त करने हेतु एआरसी में असाध्य एनपीए खातों का विपणन किया जाएगा।

सी. ऋण निगरानी

वित्तीय वर्ष 18 में नया स्लिपेज ₹12903 करोड़ था। मार्च 17 को यथास्थिति एसडीआर/एस4ए के अंतर्गत ₹3011 करोड़ का बकाया मार्च 18 में घटकर ₹498 करोड़ रह गया। 5/25 योजना के अंतर्गत बकाया ₹993 करोड़ रहा।

मार्च 17 में ₹4656 करोड़ के कुल मानक पुनःसंरचित अग्रिम मार्च 18 में घटकर ₹945 करोड़ रह गए। ₹3711 की कमी में एनपीए स्लिपेज में ₹2289 करोड़, ₹929 करोड़ का अपग्रेडेशन और बकाया/खाते बंद करने में ₹494 करोड़ की निवल कमी शामिल है।

मार्च, 17 को यथास्थिति सीडीआर, एसएमई और अन्य उद्यमों के अंतर्गत मानक पुनर्संरचना की राशि क्रमशः ₹1567 करोड़, ₹383 करोड़ और ₹2705 करोड़ थी जो मार्च 18 में घटकर शून्य, ₹44 करोड़ और ₹901 करोड़ रह गई।

- Sale of chronic/difficult accounts to ARC was another option available to tackle rising NPA. This was utilized in 216 accounts and assets worth ₹2539.21 Crore were sold to various agencies during the FY18.
- Initiatives for identifying Wilful Defaulters were undertaken in terms of guidelines of Reserve Bank of India. On completion of due diligence exercise, identified borrowers were declared as Wilful Defaulter by the Bank and the number now stands at 257, a two and half -fold jump from Mar'17 figure of only 101.
- For effective and better monitoring, all NPA borrowal accounts were categorized under four broad heads, viz. (i) Below ₹50,000 (ii) Rs.50,000 to ₹15,00 lakhs (iii) ₹15.00 lakhs to 1.00 crore and (iv) above ₹1.00 crore. While OTS is the main focus in first two stages, other additional options like sale under SARFAESI, declaration of willful Defaulter, restructuring, suit at DRT are followed very methodically for next two categories. Resolution through IBC/ NCLT are also used as important tools for recovery in high value NPA accounts. Further, for borrowal accounts having outstanding above ₹1.00 crore, monthly VC meetings are held with Zonal Heads and FGMs and 'Doable' accounts are identified where turnaround/ recovery is expected within the quarter. These accounts are then followed-up on daily basis to ensure resolutions.
- Bank has referred 65 NPA borrowal cases involving an amount of ₹12566.11 cr to NCLT for resolution under IBC during FY18.
- Tie-up with National E-governance Service Ltd. (NeSL) was done for utilizing the latter's information utility services envisaged under the IBC.

New initiates to be adopted

- A separate "NCLT Cell" at Head Office for exclusive monitoring of NCLT referred cases is being formed .
- Marketing of chronic NPA accounts among ARCs will be done to get better bids.

C. CREDIT MONITORING

Fresh Slippages to NPA in FY 18 were Rs 12903 Cr. The outstanding of ₹3011 Cr under SDR/S4A as on Mar 17 came down to ₹498 Cr in Mar 18. Under 5/25 scheme, outstanding stood at ₹993 Cr.

Total standard restructured advances of ₹4656 Cr in Mar 17 came down to ₹945 Cr in Mar 18. The reduction of ₹3711 Cr comprised ₹2289 Cr of slippages to NPA, ₹929 Cr up-gradation and ₹494 Cr net reduction in outstanding / closure of accounts.

Amount of standard restructuring under CDR, SME & other enterprises of ₹1567 Cr, ₹383 Cr and ₹2705 Cr respectively in Mar 17 was reduced to NIL, ₹44 Cr and ₹901 Cr in Mar 18

भारिबैं ने दिनांक 12 फरवरी, 2018 के अपने परिपत्र सं. भारिबैं/2017-18/131 डीबीआर सं. 101/21.04.048/2017-18 के तहत दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु संशोधित संरचना जारी की है। उक्त परिपत्र के प्रभाव के रूप में वित्तीय वर्ष 18 की चौथी तिमाही में एनपीए में स्लिपेज ₹1565 करोड़ और प्रावधान ₹645 करोड़ था। बैंक ने दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु पर्याप्त कदम उठाए हैं।

बैंक संशोधित भारिबैं दिशानिर्देशों के अनुसार खातों को एसएमए में वर्गीकृत कर रहा है और तदनुसार सीआरआईएलसी को रिपोर्ट कर रहा है।

एसएमए-0 स्तर से ही खातों की मानिटरिंग की जाती है। शाखाएं/कार्यालय विभिन्न ऋण मानिटरिंग साधनों के प्रयोग के माध्यम से ऋण मानिटरिंग में गति लाने हेतु सतत अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं जैसे यूनिट का दौरा, स्टॉक विवरण डीपी निर्धारण, स्टॉक सत्यापन, अंतिम उपयोग का सत्यापन, प्रतिभूति का दौरा और मूल्यांकन, क्यूआईएस मानिटरिंग, खाते का व्यवहार, स्टॉक लेखापरीक्षा, ऋण समीक्षा तंत्र, आवधिक विधिक लेखापरीक्षा, निरीक्षण और समवर्ती लेखापरीक्षा, सीआरआईएलसी, दैनिक एसएमए ट्रेकिंग, पूर्व चेतावनी संकेत आदि।

प्रलेखों की जांच और सत्यापन करने तथा अनियमितताओं, यदि कोई हो, को दूर करने हेतु पूर्व-संवितरण साधन के रूप में प्रलेख इलेक्ट्रानिक सत्यापन और आर्किवल (देवा) का प्रयोग किया जाता है। एलएएमपी एक अन्य आनलाइन संवितरण-पश्चात साधन है जो सभी ऋण मानिटरिंग पैरामीटरों के डाटा प्राप्त करता है, खातों की रेटिंग करता है तथा मानिटरिंग को सुविधाजनक बनाता है।

बैंक ने अपने विभिन्न नियंत्रक कार्यालयों(एफजीएमओ और मंका) में ऋण "मानिटरिंग हेतु नोडल अधिकारियों" को नामोद्दिष्ट किया है जो अपने क्षेत्र में समग्र ऋण मानिटरिंग प्रकार्यों पर नजर रखते हैं।

बैंक खातों की स्थिति में सुधार और स्लिपेज रोकने हेतु 360° ऋण मानिटरिंग हेतु प्रतिबद्ध है।

डी. डिजीटलाइजेशन

वैकल्पिक सुपुर्दगी चैनल

इंटरनेट बैंकिंग

बैंक अपने ग्राहकों को रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। 31 मार्च, 2018 को बैंक के इंटरनेट बैंकिंग ग्राहकों की संख्या 12.8 लाख तक पहुंच गई। बैंक ने वित्तीय वर्ष 18के दौरान अपनी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को अद्यतन किया है जो निम्नानुसार हैः

- अटल पेंशन योजना हेतु (एपीवाई) हेतु पंजीकरण
- मोबाइल बैंकिंग का आनलाइन पंजीकरण
- मोबाइल बैंकिंग में विभिन्न खाते जोड़ने की सुविधा
- आरटीजीएस/एनईएफटी लेनदेनों की शेड्यूलिंग
- तमिलनाडु और छत्तीसग़ढ राज्य कर भुगतान
- 15जी/15एच का आनलाइन प्रस्तुतीकरण।

मोबाइल बैंकिंग

बैंक लगभग 31 लाख ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग सुविधा प्रदान कर रहा है। वित्तीय वर्ष 18 के दौरान मोबाइल एप का अपग्रेडेड वर्जन लागू किया गया जो ग्राहकों को और अधिक सहजता से लेनदेन करने में समर्थ बनाता है। बैंक ने अपने एटीएम नेटवर्क के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग को रजिस्टर करने की सुविधा भी शुरू की है।

RBI vide its circular no. RBI/2017-18/131 DBR.No.BP.BC. 101/21.04.048/ 2017-18 dated February 12, 2018 issued Revised Frame-work for Resolution of Stressed Assets. As an impact of the said circular, slippage to NPA was ₹1565 Cr and a provision of ₹645 Cr in Q4 of FY 18. The Bank has taken adequate steps to comply with the guidelines.

The Bank is classifying accounts into SMA as per the revised RBI guidelines and reporting them on CRILC accordingly.

Monitoring of accounts is done right from SMA-0 level. The Branches / offices are continuously followed up for stepping up credit monitoring through use of various credit monitoring tools, such as Unit Visit, Stock statement & DP assessment, Stock verification, End use verification, Security Visit & Valuation, QIS monitoring, Conduct of account, Stock Audit, Loan review Mechanism, Periodic legal Audit, Inspection & Concurrent Audit, CRILC, Daily SMA tracking, Early Warning Signals etc.

Document Electronic Verification & Archival (DeVA) is used as a pre -disbursement tool to check & verify documentation & to weed out irregularities if any. LAMP is another online post-disbursement tool that captures data on all credit monitoring parameters, rates accounts and facilitates monitoring. It also provides Early Warning Signals (EWS)

Bank has designated "Nodal Officers for Credit Monitoring" in its various controlling offices (FGMO and ZO), who oversee all the credit monitoring functions in their span.

Bank is committed to 360° Credit monitoring to improve health of accounts and prevent slippage.

D. DIGITALIZATION

Alternate Delivery Channels

Internet Banking:

The Bank is providing Retail Internet banking & Corporate Internet banking facilities to its customers. The Internet Banking Customers of the Bank reached 12.8 lacs as on 31st March 2018. The Bank updated its Internet Banking Services during FY18 as under:

- Registration of Atal Pension Yojana (APY).
- Online registration of Mobile Banking
- Facility to link different accounts in Mobile Banking
- Scheduling RTGS / NEFT transactions
- Tamil Nadu & Chhattisgarh State tax payment
- Online 15G/15H submission

Mobile Banking

The Bank is providing Mobile Banking services to around 31 lakh customers. During FY18, upgraded version of the Mobile App was introduced, enabling the customers to do transactions with more ease. The Bank also introduced the facility to register for Mobile Banking through its network of ATMs.